साथियों,

भारत एक अभुत्वपुर्ण मानवीय आपदा से गुज़र रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहार पहले से ज़्यादा घातक रूप से आई है जिसके खिलाफ केंद्र सरकार हर स्तर पर लड़ने में नाकाम रही है। संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाई गई तालाबंदी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों मजदूरों की आजीविका खासतौर पर स्वास्थ्य, खाद्य एवं आर्थिक असुरक्षा पर भारी प्रभाव पड़ा है।

भारत के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी स्थापित करने की आवशयकता है। इसके साथ ही चल रहे संकट के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दों पर मांग उठाने की ज़रूरत है।

इसके उपरांत हम 1 जून 2021 से डे ऑफ एक्शन को प्रारम्भ कर रहे हैं जिसे साप्ताहिक रूप से स्वास्थ्य, भोजन तथा रोजगार की मांग को हर संभव स्तर पर सरकार के समक्ष पूरे महीने रखा जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि 1 जून का महत्वपूर्ण स्थान है जिसे अभियान द्वारा 2020 में काले दिन के रूप में मनाया गया था जहाँ हमने इसे शोक दिवस के तहत उन सभी को याद किया था जिनकी अचानक तालाबंदी के कारण मृत्यु हुई। यह मृत्यु कोविड-19 के अलावा भूख एवं प्रवासी मजदूरों के घर वापस जाने के दौरान दुर्घटना में हुई।

डे ऑफ एक्शन प्लान निम्लिखित हैं:

**1 जून से 6 जून**

घोषणा के साथ कार्यक्रम की जिसे आने वाले चार सप्ताह तक चलाया जाएगा। यह सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं अन्य माध्यमों से संभव किया जाएगा। सभी द्वारा देश भर में सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजने का कार्य स्थानीय जगह पहुँच के या फिर ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा किया जाएगा, चार्टर डिमांड के साथ प्रमुख मांगो की साप्ताहिक आयोजन के तहत करने की घोषणा।

7 जून: पहले सप्ताह के माँगों के अनुसार नेशनल वेबिनार/कार्यक्रम

दूसरा सप्ताह (8 जून-13 जून): सभी को भोजन।

 खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु PDS के सार्वभौमीकरण, तथा मध्यान भोजन, ICDS को सुचारू रूप से चलाने की मांग और इसके साथ ही खाद्य प्रणाली एवं कृषि में आए बदलाव को देखते हुए सभी को भोजन की मांग।

14 जून : खाद्य सुरक्षा एवं सभी को भोजन के तहत दूसरे सप्ताह के अंत में राष्ट्रीय वेबिनार/कार्यक्रम

तीसरा सप्ताह (15जून-20 जून): सभी को रोजगार

सभी राज्य तालाबंदी एवं कोविड महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में फैले बेरोजगारी और अव्यवस्था तथा गरीबी पर कार्यक्रमों की तैयारी। इस कार्यक्रम के साथ NREGA और उनकी मांगों को भी उठाएंगे। इसके साथ ही फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के माली हालत पर भी ध्यान रखा जाएगा।

21 जून: सभी को रोजगार के तहत तीसरे सप्ताह के अंत में राष्ट्रीय वेबिनार/कार्यक्रम

चौथा सप्ताह (22 जून): सभी को स्वास्थ्य

राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचागत गिरावट को ध्यान में रखते हुए मुफ्त, सार्वजनिक स्वास्थ सेवाओं को गारंटी के रूप में प्रदान किये जाने की माँग की जाए। कोविड मरीजों की जाँच, पहचान एवं एकांत की व्यवस्था गांव मुहल्लों में देने की माँग उठाई जाए, इसके साथ आशा कार्यकर्ताओं के लिए उचित एवं बड़े स्तर पर उनकी संख्या हर स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ाई जाए। मुफ्त टीकाकरण की माँग उठाई जाए।

नोट:

1. इसके साथ ही जवाबदेही के विषयों को प्रत्येक दिन इन साप्ताहिक कार्यक्रमों के बीच मांगों को उठाने की कोशिश करनी है (जिसमे राज्यों द्वारा अतिरिक्त राशन प्रवासी मजदूरों के लिए न उठा पाने की मांग को उठाया जा सकता है)।
2. हम सभी संगठनों एवं राज्य स्तरीय कमेटी से अनुरोध करते हैं कि वह मांग पत्र और डे ऑफ़ एक्शन तथा विषयों के अनुसार सभी के साथ जुड़ें। इन योजनाओं के साथ राज्य अपने प्रमुख विषयों एवं मांग के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं जो प्रत्येक राज्यों से अलग पाई जा सकती हैं।
3. सभी के लिए इस समय एक बड़ी सभा कर पाना संभव नही है इसलिये ऑनलाइन कार्यक्रम, छोटी मीटिंग, प्रोटेस्ट वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. समस्त कार्यक्रम मज़बूत सोशल मीडिया अभियान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। सभी सम्बंधित एवं इछुक लोगों से अनुरोध है कि वह संपर्क करें।

ज़िंदाबाद

सचिवालय, दिल्ली रोज़ी रोटी अधिकार अभियान